भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 331
2 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना के तहत लाभार्थी कंपनियां

331. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः
क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश भर में स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत लाभार्थी कंपनियों की/ सूची का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में अब तक इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी से उत्पादन की कुल मात्रा एवं मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएलआई योजना के अंतर्गत लाभार्थी-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई, जारी की गई एवं उपयोग की गई;

(घ) क्या सरकार ने पीएलआई योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया है और यदि हाँ, तो प्रस्तावित समय-सारणी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने पीएलआई योजना में कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने हेतु कोई जागरूकता अभियान चलाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ङ) : विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलाई) योजना को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹6,322 करोड़ के बजट के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से विशेष इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए उन कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है, जो निर्दिष्ट निवेश एवं उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करती हैं। यह योजना पाँच उत्पाद श्रेणियों को कवर करती है, जिनमें: कोटेड स्टील, हाई-स्ट्रेंथ स्टील, स्पेशियलिटी रेल्स, एलॉय स्टील एवं स्टील वायर, और इलेक्ट्रिकल स्टील शामिल हैं। अब तक दो चरण पूरे हो चुके हैं, जिनमें भाग लेने वाले लाभार्थी आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों से हैं। पहले और दूसरे चरण में क्रमशः 19 कंपनियों ने ₹27,106 करोड़ का निवेश और 25 कंपनियों ने ₹17,000 करोड़ का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। अक्टूबर 2025 तक, भाग लेने वाली लाभार्थी कंपनियों ने ₹23,022 करोड़ का निवेश किया है, 2.33 मिलियन टन विशेष इस्पात का उत्पादन किया है, और पात्र लाभार्थियों को ₹131.64 करोड़ प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार कर एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाती है। निवेश, क्षमता वृद्धि, रोजगार, उत्पाद पोर्टफोलियो आदि से संबंधित निर्णय कंपनियों द्वारा प्रौद्यो-वाणिज्यिक विश्लेषण पर आधारित है।

****